Q.1) एक तरलता जाल (Liquidity Trap) निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में घटित हो सकता है?

1. मुद्रास्फीति की अपेक्षा।
2. बांड्स धारण करने की अनिच्छा।
3. बचत के लिए वरीयता।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.1) Solution (c)

विकल्प 1	विकल्प 2	विकल्प 3
असत्य	**सत्य**	**सत्य**
अपस्फीति (deflation) की आशंका होने पर तरलता जाल की घटना हो सकती है। यदि अपस्फीति है या लोग अपस्फीति (कीमतों में गिरावट) की उम्मीद करते हैं तो वास्तविक ब्याज दरें काफी अधिक हो सकती हैं, भले ही नॉमिनल ब्याज दरें शून्य हों। - यदि कीमतें प्रति वर्ष 2% गिर रही हैं, तो नकदी रखने का अर्थ है कि आपके पैसे के मूल्य में वृद्धि होगी।	बांड रखने की अनिच्छा - यदि ब्याज दरें शून्य होती हैं, तो निवेशक कुछ समय में ब्याज दरों में वृद्धि की उम्मीद करेंगे। यदि ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो बांड की कीमत गिर जाएंगी। इसलिए, निवेशक बॉन्ड रखने के बजाय नकद बचत रखेंगे।	तरलता जाल मंदी की अवधि और एक उदास आर्थिक दृष्टिकोण के दौरान घटित होता है। उपभोक्ता, फर्म और बैंक भविष्य के बारे में निराशावादी होते हैं, इसलिए वे अपनी एहतियाती बचत को बढ़ाने के लिए देखते हैं तथा उन्हें व्यय करना मुश्किल होता है, जो कि मांग बनाने के लिए आवश्यक है ताकि अर्थव्यवस्था एक बार फिर से जीवित हो सके। बचत अनुपात में इस वृद्धि का अर्थ व्यय में गिरावट है।

Q.2) राजकोषीय घाटे के प्रत्यक्ष मुद्रीकरण (direct monetization of fiscal deficit) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. प्रत्यक्ष मुद्रीकरण एक लॉकडाउन जैसी घटनाओं के कारण होने वाली सकारात्मक मांग झटके की स्थिति में उपयुक्त होता है।
2. इसमें, सरकार RBI को अपने घाटे का वित्तपोषण करने के लिए नई मुद्रा मुद्रित करने के लिए कहती है।
3. यह मुद्रास्फीति में वृद्धि का कारण बन सकता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 2
d) उपरोक्त सभी

Q.2) Solution (b)

विकल्प 1	विकल्प 2	विकल्प 3
असत्य	**सत्य**	**सत्य**
प्रत्यक्ष मुद्रीकरण एक **नकारात्मक मांग** की स्थिति में उपयुक्त होता है जो लॉकडाउन जैसी घटनाओं के कारण होता है। यह उपकरण सरकार के लिए उस समय समग्र मांग को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है जब निजी मांग में गिरावट आई हो।	घाटे के प्रत्यक्ष मुद्रीकरण में, सरकार सीधे आरबीआई के साथ व्यवहार करती है। यह RBI को नए बांडों के बदले नई मुद्रा छापने के लिए कहती है जो सरकार RBI को देती है।	नए धन का उपयोग सरकारी व्यय में वृद्धि करता है तथा अर्थव्यवस्था में निजी मांग को बढ़ाता है। इस प्रकार, यह मुद्रास्फीति को बढ़ावा देता है।

Q.3) मुद्रास्फीति से निपटने के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय उपाय हैं?

1. उधार नियंत्रण
2. कर में वृद्धि
3. अनावश्यक व्यय में कमी

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1 और 2
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.3) Solution (c)

मुद्रास्फीति को मुकाबला करने के लिए राजकोषीय उपाय

- कर में वृद्धि।
- अनावश्यक व्यय में कमी।
- बचत में वृद्धि।
- अधिशेष बजट।
- सार्वजनिक ऋण।

मुद्रास्फीति को कम करने के लिए मौद्रिक उपाय

- उधार नियंत्रण।
- मुद्रा का विमुद्रीकरण।
- नई मुद्रा जारी करना।

अन्य उपाय

- उत्पादन में वृद्धि करना।
- तर्कसंगत वेतन नीति।
- मूल्य नियंत्रण।
- नियंत्रित वितरण (Rationing)।

Q.4) तरीके और साधन अग्रिम (Ways and Means Advances) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह एक प्रकार का दीर्घकालिक ऋण है जिसे सरकार केंद्रीय बैंक से उधार ले सकती है।
2. यह सरकार के राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का एक स्रोत है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.4) Solution (d)

विकल्प 1	**विकल्प 2**
असत्य	**असत्य**
तरीके और साधन अग्रिम (WMAs), आरबीआई द्वारा सरकार को प्रदान की गई अस्थायी ऋण सुविधाएं हैं, जो इसे राजस्व और व्यय के बीच अस्थायी असंतुलन को पूरा करने में सक्षम बनाती हैं। इन निधियों की उपलब्धता से अल्पकालिक व्यय करने के लिए कुछ जगह मिलेगी।	तरीके और साधन अग्रिम वित्तीय घाटे के वित्तपोषण का एक स्रोत नहीं है। समझौते के अनुसार, अर्थोपाय अग्रिम (WMAs) दिए जाने की तारीख से तीन महीने के भीतर पूरी तरह से भुगतान किया जाएगा।

Q.5) FRBM अधिनियम के तहत पलायन खंड प्रावधान (escape clause provision under the FRBM Act) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. सरकार द्वारा किए गए संरचनात्मक सुधारों के कारण, 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से सरकार विचलित हो गयी है।
2. वर्तमान कोरोनावायरस महामारी वार्षिक राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाने के लिए एक वैध आधार है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.5) Solution (c)

विकल्प 1	**विकल्प 2**
सत्य	**सत्य**
सरकार के अनुसार, 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को जीडीपी के 3.3 प्रतिशत के बजटीय लक्ष्य की तुलना में जीडीपी के 3.8 प्रतिशत पर पुनर्गठित किया गया है। सरकार द्वारा लिए गए निगम कर में कटौती जैसे	कोरोनावायरस महामारी को राष्ट्रीय आपदा माना जा सकता है। इसलिए यह वार्षिक राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाने के लिए एक वैध आधार है। पहले से ही केरल जैसे कई राज्यों ने मौजूदा स्थिति के कारण

संरचनात्मक सुधारों के कारण विचलन आवश्यक हो गया है।	FRBM लक्ष्य पर छूट मांगी है।

FRMB अधिनियम के तहत पलायन खंड

- FRBM अधिनियम के तहत राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से ऊपर जाने के रियायती प्रावधान लोकप्रिय रूप से पलायन खंड (escape clause) के रूप में जाने जाते हैं।
- अधिनियम की उप-धारा 4 (2) विभिन्न आधारों के बारे में कहती है, जिन पर FRBM के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को किसी वर्ष के दौरान छूट दी जा सकती है -
    - राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध का एक कार्य।
    - राष्ट्रीय आपदा।
    - कृषि का पतन जिससे कृषि उत्पादन और आय गंभीर रूप से प्रभावित होती है।
    - अप्रत्याशित राजकोषीय निहितार्थ के साथ अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार।
    - पिछली चार तिमाहियों के औसत से कम से कम तीन प्रतिशत अंकों की वृद्धि से एक तिमाही के वास्तविक उत्पादन वृद्धि में गिरावट।

Q.6) अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र (Renewable Energy Certificates- REC) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. एक आरईसी तब प्रदान किया जाता है, जब एक पात्र अक्षय ऊर्जा स्रोत से एक मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है।
2. यहां तक कि, छत के सौर पैनलों वाले गृहस्वामी भी आरईसी प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।
3. आरईसी की कीमत केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय की जाती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 1 और 3
c) केवल 1
d) उपरोक्त सभी

Q.6) Solution (a)

विकल्प 1	**विकल्प 2**	**विकल्प 3**
सत्य	**सत्य**	**असत्य**
अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र (RECs) एक बाजार आधारित उपकरण है जो वाहक को प्रमाणित करता है, जो अक्षय ऊर्जा संसाधन से उत्पन्न एक मेगावाट-घंटे (MWh) बिजली उत्पादित करता है। एक बार जब बिजली प्रदाता, ऊर्जा को ग्रिड में फीड कर देता है, तो आरईसी प्राप्त ऊर्जा के रूप में खुले बाजार में बेची जा सकती है।	नवीकरणीय बिजली का प्रदाता, जिसमें छत के सौर पैनलों वाले गृहस्वामी आरईसी प्राप्त करने के पात्र हैं।	अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र (RECs) एक बाजार आधारित उपकरण है। आपूर्ति और मांग के कारण कीमत भिन्न हो सकती है। हालांकि, वे केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) द्वारा निर्दिष्ट 'floor price' (न्यूनतम मूल्य) और 'forbearance price' (अधिकतम मूल्य) के बीच समाहित होती हैं।

- REC सौर, पवन और अन्य हरित ऊर्जा के लिए एक ट्रैकिंग तंत्र के रूप में कार्य करता है क्योंकि वे पावर ग्रिड में प्रवाहित होते हैं।
- REC कई नामों से जाते हैं, जिनमें ग्रीन टैग, ट्रेडेबल रिन्यूएबल सर्टिफिकेट (टीआरसी), रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी सर्टिफिकेट या रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट शामिल हैं।
- भारत में, REC का कारोबार दो पावर एक्सचेंजों- Indian Energy Exchange (IEX) और पावर एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया (PXIL) पर किया जाता है।

Q.7) RBI द्वारा आयोजित विदेशी मुद्रा विनिमय नीलामी (Foreign exchange swap auction) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. इसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में अस्थिरता को कम करना था।
2. यह प्रणाली में बढ़ती तरलता का प्रभाव है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.7) Solution (b)

विकल्प 1	**विकल्प 2**
असत्य	**सत्य**
विदेशी मुद्रा विनिमय का उद्देश्य प्रणाली की टिकाऊ तरलता आवश्यकताओं को पूरा करना है।	विनिमय लंबी अवधि के लिए विदेशी मुद्रा खरीदने / बेचने के माध्यम से लंबी अवधि के लिए रुपये की तरलता को इंजेक्ट करता है। विदेशी मुद्रा विनिमय अनिवार्य रूप से बैंकों के हाथों में अधिक पैसा डालता है।

विदेशी मुद्रा विनिमय नीलामी (Forex swap auction)

- आरबीआई ने 3 साल के लिए बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा विनिमय नीलामी के माध्यम से प्रणाली में दीर्घकालिक तरलता का समामेलन (injected) किया है।
- विनिमय के तहत, एक बैंक RBI को अमेरिकी डॉलर बेचेगा। यह उसी समय (simultaneously) विनिमय अवधि के अंत में अमेरिकी डॉलर की समान राशि खरीदने के लिए सहमत होगा।
- विनिमय लेनदेन ओएमओ (खुले बाजार के संचालन) से भौतिक रूप से भिन्न होता है जिसमें आरबीआई खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता है और बेचता है।

Q.8) दीर्घ आवधिक रेपो संचालन (Long Term Repo Operation- LTRO) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. LTRO के माध्यम से उधार ली गई निधि पर, बैंक दर से उधार ली गई निधि से कम ब्याज दर होती है।
2. LTRO सुविधा का लाभ उठाने के लिए केवल सरकारी प्रतिभूतियों को संपार्श्विक (collateral) के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
3. LTRO कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश को बढ़ावा देगा।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 1 और 2
c) केवल 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.8) Solution (d)

विकल्प 1	विकल्प 2	विकल्प 3
सत्य	सत्य	सत्य
आमतौर पर, रेपो दर बैंक दर से कम होती है। वर्तमान रेपो दर 4.40% है जबकि बैंक दर 4.65% है।	LTRO एक ऐसा उपकरण है जिसके तहत केंद्रीय बैंक प्रचलित रेपो दर पर बैंकों को एक साल से तीन साल का पैसा मुहैया कराता है, जो सरकारी प्रतिभूतियों को संपार्श्विक के रूप में मिलान या उच्चतर कार्यकाल के साथ स्वीकार करता है।	LTRO से अल्पकालिक दरों को कम करने और कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश को बढ़ावा देने की उम्मीद होती है

Q.9) सरकार ने हाल ही में आवश्यक वस्तु अधिनियम (ECA) के दायरे में हैंड सैनिटाइजर और मास्क लाए हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें

1. अधिनियम राज्य सरकारों को भी कुछ वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।
2. औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (DPCO), ECA की शक्तियों के तहत जारी किया जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.9) Solution (c)

विकल्प 1	विकल्प 2
सत्य	सत्य
अधिनियम ECA में सूचीबद्ध कुछ वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को समवर्ती रूप से सशक्त बनाता है। अधिनियम के प्रावधान के तहत जो उपाय किए जा सकते हैं, उनमें लाइसेंसिंग, वितरण और स्टॉक, अन्य सीमाएं शामिल हैं।	औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 1995 दवाओं की कीमतों को विनियमित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत भारत सरकार द्वारा जारी एक आदेश है। DPCO के प्रावधानों को लागू करने के लिए, सरकार की शक्तियाँ एनपीपीए (राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण) में निहित है।

Q.10) कृषि क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. एक किसान उत्पादक संगठन कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत एक कानूनी संस्था है।
2. पशुधन, मुर्गीपालन और मत्स्य पालन को मॉडल अनुबंध खेती अधिनियम 2018 के दायरे में शामिल किया गया है।
3. हाल ही में, तमिलनाडु अनुबंध खेती पर एक कानून बनाने वाला पहला राज्य बना है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.10) Solution (c)

विकल्प 1	**विकल्प 2**	**विकल्प 3**
असत्य	**सत्य**	**सत्य**
एक उत्पादक संगठन (PO) एक कानूनी संस्था है जिसका गठन प्राथमिक उत्पादकों किसान, दूध उत्पादक, मछुआरे, बुनकर, ग्रामीण कारीगर, शिल्पकार आदि द्वारा किया जाता है। संस्था को सहकारी समितियों अधिनियम के तहत सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है या कंपनी अधिनियम के तहत उत्पादक कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।	मॉडल अनुबंध कृषि अधिनियम 2018 में कृषि और बागवानी फसलों, पशुधन, डेयरी, पोल्ट्री और मत्स्य पालन की सभी श्रेणियां शामिल हैं।	हाल ही में, तमिलनाडु अनुबंध खेती पर एक कानून बनाने वाला पहला राज्य बना है।

Q.11) नामकरण के हार्मोनाइज्ड सिस्टम (Harmonized System of Nomenclature- HSN) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. यह एक बहुउद्देशीय अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद नामकरण है जिसे विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा विकसित किया गया है।
2. माल-भाड़ा टैरिफ (freight tariffs) जैसे उद्देश्यों के लिए निजी क्षेत्र की फर्मों द्वारा कोड का उपयोग किया जाता है।
3. भारत ने हाल ही में, सीमा शुल्क के प्रयोजनों के लिए माल के वर्गीकरण हेतु HSN का पालन करने का निर्णय किया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2
c) केवल 1 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.11) Solution (a)

विकल्प 1	विकल्प 2	विकल्प 3
सत्य	**सत्य**	**असत्य**
यह एक बहुउद्देशीय अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद नामकरण है जिसे विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा विकसित किया गया है। यह वस्तु के प्रकार का वर्णन करने के लिए विश्व भर में सामान्य मानक है	इसका उपयोग न केवल सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा किया जाता है, बल्कि निजी क्षेत्रों द्वारा कई अन्य उद्देश्यों जैसे आंतरिक करों, माल भाड़े के शुल्क, परिवहन सांख्यिकी, अनुसंधान और विश्लेषण के लिए भी किया जाता है।	भारत ने एक दशक से अधिक समय से सीमा शुल्क के प्रयोजनों के लिए माल के वर्गीकरण के लिए एचएसएन का पालन किया है। हाल ही में, सरकार ने HSN कोड के बिना आयात की अनुमति नहीं देने का निर्णय किया है।

Q.12) प्रतिभूतिकरण (Securitization) शब्द कभी-कभी समाचारों में देखा जाता है। यह निम्न में से किसको संदर्भित करता है

a) राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के लिए सरकारी प्रतिभूति जारी करना।
b) समेकित वित्तीय साधन में वित्तीय परिसंपत्तियों की पूलिंग।
c) डिफ़ॉल्ट की अपेक्षा के कारण सरकारी प्रतिभूति रखने की अनिच्छा।
d) गैर-निष्पादित परिसंपत्ति मुद्दे को कम करने के लिए असुरक्षित ऋण से सुरक्षित ऋण में रूपांतरण।

Q.12) Solution (b)

प्रतिभूतिकरण (Securitization)

- प्रतिभूतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक कंपनी एक समेकित वित्तीय साधन बनाने के लिए विभिन्न वित्तीय परिसंपत्तियों / ऋणों को जमा करती है जो निवेशकों को जारी किया जाता है।
- यह फर्म को पूंजी जुटाने में सक्षम बनाता है तथा इस प्रकार बाजार में तरलता को बढ़ाता है।
- प्रतिभूतिकरण में बिक्री योग्य प्रतिभूतियों में कम तरल संपत्तियों का पुन:स्थापन शामिल होता है।

Q.13) भारत ने हाल ही में, कर संधि से संबंधित उपायों (MLI) को लागू करने के लिए बहुपक्षीय कन्वेंशन की पुष्टि की है। इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. MLI आधार क्षरण और लाभ हस्तांतरण तथा धन शोधन से निपटने के लिए OECD और FATF प्रोजेक्ट का एक परिणाम है।
2. MLI "आरक्षण" जैसे प्रावधानों के माध्यम से लचीलापन प्रदान करता है
3. MLI हस्ताक्षरकर्ता देशों के बीच किसी भी मौजूदा द्विपक्षीय कर संधि समझौतों को संशोधित नहीं करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है / हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.13) Solution (b)

विकल्प 1	विकल्प 2	विकल्प 3

असत्य	सत्य	असत्य
बहुपक्षीय कन्वेंशन आधार क्षरण और लाभ हस्तांतरण से निपटने के लिए OECD/G20 परियोजना का एक परिणाम है।	MLI "आरक्षण" जैसे प्रावधानों के माध्यम से लचीलापन प्रदान करता है। इसके माध्यम से, देश कुछ MLI प्रावधानों को लागू करने का विकल्प चुन सकते हैं।	MLI उन कर संधियों को संशोधित करती है, जो "कवर किए गए कर समझौते" होते हैं।

कवर किए गए कर समझौता (Covered Tax Agreement)

- कवर किए गए कर समझौते का अर्थ है कि दोहरे कराधान से बचने के लिए एक समझौता, जो कि पार्टियों के बीच MLI के लिए लागू होता है, जिसे दोनों पक्षों ने एक अधिसूचना दी है कि वे MLI का उपयोग करके समझौते को संशोधित करना चाहते हैं।

Q.14) ई-नाम (e-NAM) प्लेटफॉर्म में हालिया सुधारों के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. किसान अब अपनी उपज को भौतिक रूप से एपीएमसी मंडियों में लाए बिना ई-नाम पर व्यापार कर सकते हैं।
2. सभी किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को अपनी उपज को चयनित भण्डारण विकास और नियामक प्राधिकरण (WDRA) के पंजीकृत गोदामों में संग्रहीत करने की आवश्यकता है।
3. बड़े लॉजिस्टिक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म को ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए प्रावधान किया गया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) केवल 3

Q.14) Solution (d)

विकल्प 1	विकल्प 2	विकल्प 3
असत्य	असत्य	सत्य
केवल वे ही किसान जो अपनी उपज को पंजीकृत भंडारगृहों में संग्रहीत करते हैं तथा e-NWR होने से e-NAM पर व्यापार करने में सक्षम होंगे, ताकि उपज को एपीएमसी में भौतिक रूप से न लाना पड़े।	किसान उत्पादकों के संगठन (FPOs) को अपनी उपज को चयनित WDRA पंजीकृत गोदामों में रखने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, अब वे बोली लगाने के लिए अपने आधार / संग्रह केंद्रों से अपने उत्पादन और गुणवत्ता मानकों की तस्वीर अपलोड कर सकते हैं।	उपयोगकर्ताओं को विकल्प प्रदान करने वाले बड़े लॉजिस्टिक एग्रीगेटर प्लेटफार्मों को जोड़ने के लिए एक प्रावधान किया गया है। व्यापारी रसद प्रदाता की वेबसाइट पर नेविगेट करने और उचित सेवाओं का चयन करने के लिए लिंक का उपयोग करने में सक्षम होंगे।

ई-नाम में हालिया सुधारों के लाभ

- जमाकर्ता लॉजिस्टिक खर्चों को बचा सकता है और बेहतर आय होगी।

- किसान मंडी में जाने की परेशानी के बिना उपज को बेहतर मूल्य पर राष्ट्र भर में बेच सकते हैं।
- यह मंडियों में भीड़ कम करेगा और परेशानी को भी कम करेगा।
- यह एफपीओ को व्यापार करने में आसानी के साथ ऑनलाइन भुगतान सुविधा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा।

Q.15) विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. हालांकि SEZ इकाइयां शुल्क के भुगतान के बिना घरेलू टैरिफ क्षेत्र (DTA) से माल आयात कर सकती हैं, हालांकि, वे DTA को माल निर्यात करने के लिए लागू शुल्क का भुगतान करते हैं।
2. सिंगल-ब्रांड खुदरा विक्रेताओं द्वारा SEZ में इकाइयों से खरीदे गए सामान, यदि लागू हो, तो स्थानीय सोर्सिंग मानदंडों को पूरा करने के लिए योग्य होंगे।
3. SEZ इकाइयां जो सकारात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन नहीं करती हैं, एक दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगी।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.15) Solution (d)

विकल्प 1	**विकल्प 2**	**विकल्प 3**
सत्य	**सत्य**	**सत्य**
SEZ इकाइयां ज़ोन में इकाइयों की स्थापना, संचालन और रखरखाव के लिए शुल्क के भुगतान के बिना DTA से वस्तुओं और सेवाओं का आयात / खरीद कर सकती हैं। हालांकि, एक SEZ इकाई लागू शुल्क के भुगतान पर आयात नीति के अनुसार माल, उप-उत्पादों और सेवाओं सहित सामान बेच सकती है।	DPIIT ने हाल ही में स्पष्ट किया कि विदेशी कंपनियों के स्वामित्व वाले एकल-ब्रांड खुदरा विक्रेताओं द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) में इकाइयों से खरीदे गए सामान, अनिवार्य 30% स्थानीय सोर्सिंग मानदंडों को पूरा करने के लिए योग्य होंगे। 51% से अधिक एफडीआई के साथ सिंगल ब्रांड रिटेल के लिए 30% स्थानीय सोर्सिंग अनिवार्य है।	SEZ इकाई एक सकारात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन होगी। NFE को उत्पादन शुरू होने से पांच वर्ष की अवधि के लिए संचयी रूप से गणना की जाएगी। सकारात्मक विदेशी मुद्रा अर्जित करने में विफलता की स्थिति में यह एक दंड के लिए उत्तरदायी होगी।

Q.16) प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह एक अम्ब्रेला योजना है जो किसानों को आय सहायता प्रदान करेगी।
2. कपास को प्राइस डेफिसिएंसी पेमेंट स्कीम के तहत कवर किया गया है।
3. मूल्य समर्थन योजना के तहत फसलों की भौतिक खरीद नहीं होगी।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2
c) केवल 3
d) इनमें से कोई भी नहीं

Q.16) Solution (b)

विकल्प 1	विकल्प 2	विकल्प 3
असत्य	**सत्य**	**सत्य**
PM-AASHA एक नई अम्ब्रेला योजना है जो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) आश्वासन प्रदान करेगी। **यह एक मूल्य समर्थन योजना है तथा आय समर्थन योजना नहीं है।**	पीडीपीएस में सभी तिलहन शामिल हैं जिनकी एमएसपी अधिसूचित किया गया है। कपास को एक तिलहनी माना जाता है क्योंकि उसमें से तेल निकाला जा सकता है। इसलिए, कपास पीडीपीएस के अंतर्गत आता है।	PSS के तहत, केंद्रीय नोडल एजेंसियां राज्य सरकारों की सक्रिय भूमिका के साथ दालों, तिलहन और कोपरा (copra) की खरीद करेंगी। हालांकि, प्राइस डेफिसिएंसी पेमेंट स्कीम के तहत कवर की गयी फसलों की कोई भौतिक खरीद नहीं होगी।

Q.17) सरकार ने हाल ही में PM-KISAN योजना के तहत 15841 करोड़ रुपये वितरित किए हैं। PM-KISAN योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. लाभार्थी की पहचान सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना -2011 के आंकड़ों के माध्यम से की जाती है।
2. 4 हेक्टेयर से अधिक भूमि रखने वाले बड़े किसानों को योजना से बाहर रखा गया है।
3. सभी PM-KISAN लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) दिया जाएगा।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 3
d) उपरोक्त सभी

Q.17) Solution (c)

विकल्प 1	विकल्प 2	विकल्प 3
असत्य	**असत्य**	**सत्य**
यद्यपि पीएम-किसान एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, लाभार्थी किसान परिवारों की पहचान की जिम्मेदारी संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों के साथ है।	6,000 / - रु. प्रति वर्ष की आय सहायता देश भर के सभी भूमिहीन किसान परिवारों को प्रदान की जाती है, भले ही भूमि का आकार कुछ भी हो, सिवाय इसके कि वे एक अपवर्जन मानदंड (exclusion criteria) के अंतर्गत नहीं आते हों।	सभी पीएम-किसान लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) दिए जाएंगे ताकि किसान बैंकों से आसानी से कर्ज ले सकें। इससे ऐसे सभी किसानों को फसल और पशु / मछली पालन के लिए अल्पकालिक ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

Q.18) राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना (National Rural Economic Transformation Project) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. इसके कार्यान्वयन के लिए सरकार पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक (IBRD) से ऋण प्राप्त करेगी।

2. परियोजना ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास कार्यक्रमों का समर्थन करेगी।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.18) Solution (a)

विकल्प 1	**विकल्प 2**
सत्य	**असत्य**
विश्व बैंक और भारत सरकार ने NREPT के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक (IBRD) से $ 250 मिलियन का ऋण, जिसकी 5 वर्षों की अनुग्रह अवधि और 20 वर्षों की अंतिम परिपक्वता है।	NERTP अपने व्यक्तिगत और / या सामूहिक रूप से स्वामित्व और प्रबंधित उद्यमों के निर्माण के लिए स्टार्ट-अप वित्तपोषण विकल्पों सहित वित्त का उपयोग करने के लिए एक मंच बनाकर ग्रामीण गरीब महिलाओं और युवाओं के लिए उद्यम विकास कार्यक्रमों का समर्थन करेगा। यह युवा कौशल विकास का भी समर्थन करेगा।

Q.19) परियोजना निगरानी समूह (Project Monitoring Group) निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है

a) गैर-निष्पादित परिसंपत्ति परियोजनाओं की निगरानी के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एक संघ।
b) सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं में बाधाओं का समाधान करने के लिए संस्थागत तंत्र।
c) एक नागरिक समाज संगठन, जो बुनियादी ढांचे के विकास के क्षेत्र में काम करता है।
d) मिशन मोड परियोजनाओं की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित एक विशेष कार्य बल।

Q.19) Solution (b)

परियोजना निगरानी समूह (Project Monitoring Group)

- परियोजना निगरानी समूह (PMG) भारत में 500 करोड़ रुपये के निवेश के साथ परियोजनाओं में मुद्दों और विनियामक बाधाओं के शीघ्र समाधान के लिए एक संस्थागत तंत्र है।
- वर्तमान में, पीएमजी इन्वेस्ट इंडिया, उद्योग विभाग और आंतरिक व्यापार (DPIIT), वाणिज्य मंत्रालय में स्थित है।
- पीएमजी सभी मध्य और बड़े आकार के सार्वजनिक, निजी और ‘ सार्वजनिक-निजी भागीदारी’ (पीपीपी) परियोजनाओं के संबंध में अनसुलझे परियोजना मुद्दों को सूचीबद्ध करना चाहता है।
- DPIIT को चुनौतियों का सामना करने वाली सार्वजनिक और निजी परियोजनाओं की समीक्षा के लिए नोडल निकाय के रूप में प्राधिकृत किया गया है तथा पीएमजी के माध्यम से उनके संकल्प को सुगम बनाता है।
- पीएमजी द्वारा उठाए गए मुद्दे संघ और राज्य-स्तर दोनों पर होते हैं।

Q.20) इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvIts) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. उन्हें आर्थिक मामलों के विभाग के तहत अवसंरचना नीति और वित्त प्रभाग द्वारा विनियमित किया जाता है।
2. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को InvIts में निवेश करने से रोक दिया गया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.20) Solution (d)

विकल्प 1	**विकल्प 2**
असत्य	**असत्य**
Invits भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित किया जाता है, न कि आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा। वे एक शेयर के समान द्वितीयक बाजार पर कारोबार करते हैं।	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को REITs और InvIts की इकाइयों में निवेश करने की अनुमति है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (Invits)

- एक इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (Invits) एक म्यूचुअल फंड की तरह है, जो कि रिटर्न के रूप में आय के एक छोटे हिस्से को अर्जित करने के लिए बुनियादी ढांचे में संभावित व्यक्तिगत / संस्थागत निवेशकों से छोटी मात्रा में धन का प्रत्यक्ष निवेश करने में सक्षम बनाता है।
- बुनियादी ढांचा क्षेत्र की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप डिजाइन किए गए REITs के संशोधित संस्करण के रूप में InvITs को माना जा सकता है।
- वे REITs के समान हैं, लेकिन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे कि सड़कों या राजमार्गों में निवेश करते हैं जो स्थिर नकदी प्रवाह उत्पन्न करने में कुछ समय लेते हैं।

Q.21) अंबुबाची मेले के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह तब मनाया जाता है जब देवी कामाख्या मासिक धर्म के अपने वार्षिक चक्र से गुजरती हैं।
2. कामाख्या मंदिर गंगा नदी के तट पर नीलाचल पहाड़ियों पर स्थित है।
3. कामाख्या मंदिर दक्षिण एशिया में फैले प्रमुख 51 शक्तिपीठों में से एक है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?
a) केवल 1 और 3
b) केवल 2
c) केवल 2 और 3
d) 1, 2 और 3

Q.21) Solution (a)

- अंबुबाची मेला प्रत्येक वर्ष जून में गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है, जिसके दौरान देवी को मासिक धर्म के वार्षिक चक्र के माध्यम से जाना माना जाता है।
- अंबुबाची मेला, जिसे अम्बुबासी त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है, तांत्रिक पंथ से निकटता से जुड़ा हुआ है तथा इसे कामाख्या देवी पूजा के रूप में भी जाना जाता है।
- कामाख्या मंदिर **ब्रह्मपुत्र नदी के तट** पर नीलाचल पहाड़ियों पर स्थित है

- अंबुबाची मेला के दौरान पूरे क्षेत्र में मंदिर तीन दिनों तक बंद रहते हैं तथा कृषि कार्य जैसे कि खुदाई, जुताई और फसलों की बुवाई करना मना होता है।
- कामाख्या मंदिर, दक्षिण एशिया में फैले प्रमुख 51 शक्तिपीठों में से एक है, जो भगवान शिव की पत्नी के एक भाग का प्रतिनिधित्व करती हैं।
- कामाख्या के गर्भगृह को तांत्रिक पूजा के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक माना जाता है, जिसमें एक चट्टान द्वारा प्रस्तुत की गई महिला या महिला जननांग है।
- जब मंदिर के दरवाज़े खोले जाते हैं, तो भक्त मंदिर के बाहर प्रतीक्षा करते हैं, जो कि अद्वितीय 'प्रसाद' के रूप में होता है, जो कपड़े के छोटे टुकड़े होते हैं, जो देवी कामाख्या के मासिक धर्म द्रव के साथ नम होते हैं। इसे अत्यधिक शुभ और शक्तिशाली माना जाता है।

Q.22) निम्नलिखित में से कौन दक्षिण एशियाई जलवायु आउटलुक फोरम (SASCOF) का हिस्सा है?

1. अफ़ग़ानिस्तान
2. बांग्लादेश
3. भूटान
4. म्यांमार
5. थाईलैंड

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

a) केवल 1, 2, 3 और 4
b) केवल 1, 2 और 3
c) केवल 2 और 3
d) 1, 2, 3, 4 और 5

Q.22) Solution (a)

- दक्षिण एशियाई जलवायु आउटलुक फोरम (SASCOF) 2010 में स्थापित किया गया था तथा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा समन्वित है।
- इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं।
- सभी SASCOF के दौरान मुख्य गतिविधि दक्षिण एशिया में दक्षिण-पश्चिम मानसून वर्षा के लिए एक आम सहमति दृष्टिकोण की तैयारी और लागु करना था।

SASCOF के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- क्षेत्रीय और वैश्विक रूप से दक्षिण एशियाई मानसून की समझ और दीर्घ आवधिक भविष्यवाणी में हुई प्रगति की समीक्षा करना
- दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और संबंधित भविष्यवाणियों पर उपलब्ध जानकारी का आकलन करना तथा प्रसार के लिए आम सहमति आधारित मौसमी दृष्टिकोण तैयार करना
- दक्षिण एशियाई मॉनसून और उनकी भविष्यवाणी पर अनुभव और ज्ञान साझा करना तथा साझा करने के लिए हितधारकों के लिए एक मंच प्रदान करना
- विशेष रूप से मौसमी भविष्यवाणी में दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए क्षमता निर्माण / मानव संसाधन विकास गतिविधियों को आरंभ करना
- आपसी लाभ के लिए एसएएससीओएफ के सदस्यों के बीच सहयोग और साझेदारी का निर्माण करना
- विभिन्न समूहों के बीच एक संवाद के माध्यम से उपयोगकर्ता क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पहचान करना।

Q.23) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. लिफ्ट सिंचाई (Lift irrigation), सिंचाई की एक विधि है जिसमें पानी को प्राकृतिक प्रवाह द्वारा अपवाहित नहीं किया जाता है बल्कि पंप या अन्य यांत्रिक साधनों से लिफ्ट किया जाता है।
2. कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना संसार की सबसे बड़ी बहु-चरण लिफ्ट सिंचाई परियोजना है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.23) Solution (c)

- लिफ्ट सिंचाई, सिंचाई की एक विधि है जिसमें प्राकृतिक प्रवाह (जैसे कि गुरुत्वाकर्षण-आधारित नहर प्रणालियों) में परिवहन के बजाय पानी को पंप या अन्य यांत्रिक साधनों का उपयोग करके पशु, ईंधन आधारित या विद्युत शक्ति के माध्यम से बाहरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
- लिफ्ट सिंचाई योजनाओं को दो मुख्य कार्यों को पूरा करना होगा: पहला, पानी के स्रोत से पंपों को मुख्य वितरण कक्ष तक ले जाने के लिए, जो कमांड क्षेत्र में सबसे ऊपरी बिंदु पर स्थित होता है। दूसरा, उन्हें इस पानी को एक उपयुक्त और उचित वितरण प्रणाली के माध्यम से लाभार्थी किसानों के खेत में वितरित करना चाहिए।

गोदावरी की बाढ़ के पानी का दोहन करने के लिए भारत के कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, तेलंगाना को सूखाग्रस्त मुक्त बनाने के उद्देश्य से है।

- कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना (KLIP) विश्व की सबसे बड़ी बहु-चरण लिफ्ट सिंचाई परियोजना है।
- गोदावरी के पानी को रिवर्स पम्पिंग और स्टोरेज द्वारा टैप किया जाएगा, जिससे 38 लाख एकड़ में कृषि की सुविधा होगी, जिसमें लगभग 18 लाख एकड़ में नई अय्याक का निर्माण, हजारों टंकियों को फिर से जीवंत करने, उद्योगों के लिए पानी उपलब्ध कराने तथा हैदराबाद और सिकंदराबाद स्टोरेज टैंक और पाइपलाइनों का एक नेटवर्क बनाने सहित पीने के पानी की आपूर्ति शामिल है।
- वर्तमान तक, विश्व में सबसे बड़ी लिफ्ट योजनाएं अमेरिका में कोलोराडो लिफ्ट योजना और मिस्र में ग्रेट मैनमेड नदी थीं।
- कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, एक भारतीय लिफ्ट योजना क्षमता के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी योजना बन गई है।
- गोदावरी नदी के पार, KLIP पानी को आधा किलोमीटर की ऊंचाई तक उठाएगा।
- इसे एक वर्ष में दो फसलों के लिए 45 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो राज्य की 70 प्रतिशत पेयजल की आवश्यकता को पूरा करता है और उद्योग की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है।

Q.24) न्यू अम्ब्रेला एंटीटीज (New Umbrella Entities- NUE) शब्द को कभी-कभी समाचारों में, किसके संदर्भ में देखा जाता है:

a) यह स्मार्ट शहरी मिशन के तहत एक प्रस्तावित संगठन है।
b) यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्थापित एक प्रस्तावित डिजिटल रिटेल भुगतान संगठन है।
c) यह भारत सरकार द्वारा सभी सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं को इसके अंतर्गत लाने का एक प्रस्तावित संगठन है
d) इनमें से कोई भी नहीं

Q.24) Solution (b)

- भारतीय रिज़र्व बैंक एक वैकल्पिक डिजिटल खुदरा भुगतान संगठन स्थापित करने का प्रस्ताव कर रहा है, क्योंकि इसका लक्ष्य उस प्रणाली में एकाधिकार को रोकना है जो वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड द्वारा वर्चस्वीकृत है।
- 'न्यू अम्ब्रेला एंटीटीज' (एनयूई), विशेष रूप से खुदरा क्षेत्र में नए भुगतान प्रणालियों की स्थापना, प्रबंधन और संचालन करेगी।
- यह भारत के डिजिटल भुगतान परिदृश्य के "एकाग्रता जोखिम" की रोकथाम के लिए आवश्यक है, जहां भुगतान चैनलों को जारी करने और नियंत्रित करने का जनादेश भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ((NPCI) द्वारा काफी हद तक एकाधिकार है।
- भुगतान ऑपरेटर या सेवा प्रदाता के रूप में काम करने वाले कम से कम तीन वर्षों के अनुभव वाले केवल एक प्रमोटर समूह के रूप में आवेदन कर सकते हैं।
- ये इकाइयां या तो 'लाभ के लिए' हो सकती हैं या एनपीसीआई जैसी गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत हो सकती हैं।
- NUE को हमेशा 300 करोड़ रुपये का न्यूनतम शुद्ध मूल्य बनाए रखना चाहिए।
- NUE को नई भुगतान विधियों, मानकों और प्रौद्योगिकियों को विकसित करने तथा समाशोधन और निपटान प्रणालियों को संचालित करने के लिए एक जनादेश भी दिया जाएगा।
- प्रस्तावित इकाई में बोर्ड पर एक आरबीआई द्वारा नियुक्त स्वतंत्र निदेशक भी होगा।
- भुगतान और निपटान प्रणाली (बीपीएसएस) के विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड, NUE की स्थापना के लिए प्राधिकरण जारी करने पर अंतिम प्राधिकारी होगा।

Q.25) राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह केंद्र सरकार द्वारा 2020-25 में पांच वर्ष की अवधि के लिए चिन्हित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए अनावरण की गई निवेश योजना है।
2. इसमें आर्थिक और सामाजिक दोनों बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शामिल हैं।
3. NIP का वित्तपोषण केंद्र, राज्यों और निजी क्षेत्रों द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 1
c) केवल 2 और 3
d) 1, 2 और 3

Q.25) Solution (d)

- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, केंद्र सरकार द्वारा 2020-25 पांच वर्ष की अवधि के लिए चिन्हित किए गए क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए अनावरण की गई निवेश योजना है।
- एनआईपी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर एक अग्रगामी दृष्टिकोण को सक्षम करेगा जो रोजगार पैदा करेगा, जीवनयापन में आसानी करेगा, और सभी के लिए बुनियादी ढांचे को समान पहुंच प्रदान करेगा, जिससे विकास और अधिक समावेशी होगा। एनआईपी में आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शामिल हैं।
- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का वित्तपोषण केंद्र, राज्यों और निजी क्षेत्र द्वारा संयुक्त रूप से 39:39:22 (केंद्र और राज्यों द्वारा 39% और निजी क्षेत्र द्वारा 22%) के अनुपात में किया जाएगा।
- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर टास्क फोर्स, जिसकी अध्यक्षता आर्थिक मामलों के विभाग (DEA), वित्त मंत्रालय (MoF) ने की है, ने बुनियादी ढांचे की योजना पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
- टास्क फोर्स का मुख्य कार्य तकनीकी रूप से व्यवहार्य और वित्तीय / आर्थिक रूप से व्यवहार्य अवसंरचना परियोजनाओं की पहचान करना था, जो 2020 से 2025 राजकोषीय वर्षों में आरंभ की जा सकती हैं।

- टास्क फोर्स ने पाया कि 2030 तक, भारत की लगभग 42% आबादी वर्तमान 31% से शहरीकृत हो जाएगी। इसलिए, शहरी बुनियादी ढांचे का भी आधुनिकीकरण किया जाना है।

Q.26) निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से सुमेलित है?

1. अगस्त्यवनम जैविक उद्यान - तमिलनाडु
2. देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य - असम
3. उष्णकटिबंधीय तितली कंज़र्वेटरी - केरल

सही कूट का चयन करें:

a) 1 और 2
b) केवल 2
c) 2 और 3
d) 1 और 3

Q.26) Solution (b)

अगस्त्यवनम जैविक उद्यान - केरल
देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य - असम
उष्णकटिबंधीय तितली संरक्षिका/ कंज़र्वेटरी - तमिलनाडु

Q.27) 'प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय' के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. भारत में 1999 से एक प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) है।
2. PSA का कार्यकाल तीन वर्ष होता है।

सही कथनों का चयन करें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.27) Solution (a)

भारत में 1999 से एक प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) हैं।

- डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम 1999-2001 तक पहले पीएसए थे
- डॉ. आर. चिदंबरम, डॉ. कलाम के उत्तरधिकारी थे तथा 2001-2018 तक पीएसए थे।
- प्रोफेसर के. विजयराघवन 3 अप्रैल, 2018 को डॉ. चिदंबरम के उत्तराधिकारी बने और वर्तमान पीएसए हैं।

Q.28) मेकांग नदी किस देश में नहीं बहती है

a) मलेशिया
b) लाओस
c) वियतनाम
d) कंबोडिया

Q.28) Solution (a)

यह नदी चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से होकर गुजरती है।

Q.29) 'मुद्रीकरण घाटे' (Monetising deficit) के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. यह आरबीआई द्वारा प्राथमिक बाजार से सीधे सरकारी बॉन्ड खरीदने और अधिक धन छापकर इस ऋण का वित्तपोषण करने की क्रिया को दर्शाता है।
2. इससे मुद्रास्फीति बढ़ सकती है तथा भारतीय रुपये का अवमूल्यन या कमजोर हो सकता है।

सही कथनों का चयन करें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.29) Solution (c)

मुद्रीकृत घाटा वह मौद्रिक सहायता है जो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) सरकार के उधार कार्यक्रम के हिस्से के रूप में केंद्र तक पहुंचाता है। दूसरे शब्दों में, यह शब्द केंद्रीय बैंक द्वारा सरकार की व्यय संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकारी बॉन्ड की खरीद को संदर्भित करता है।

यह ऋण मुद्रीकरण के रूप में भी जाना जाता है, इस अभ्यास से प्रणाली में कुल धन की आपूर्ति में वृद्धि होती है, तथा इसलिए मुद्रास्फीति बढ़ती है, क्योंकि RBI बांड खरीदने के लिए नए पैसे का मुद्रण करता है। बाद में उसी बॉन्ड का उपयोग मुद्रास्फीति को नीचे लाने के लिए किया जाता है क्योंकि वे खुले बाजार में बेचे जाते हैं। इससे RBI को बाजार से अतिरिक्त धन प्राप्त करने और बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने में मदद मिलती है।

तर्क यह है कि अत्यधिक घाटे का मुद्रीकरण, मुद्रा का अवमूल्यन कर सकता है, जिससे विदेशी निवेशक आत्मविश्वास खो देते हैं और धन बाहर निकाल लेते हैं तथा मौजूदा वित्तीय वित्तपोषण योजना को जोखिम में डालते हैं।

Do Read This - https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/indicators/view-monetisation-of-deficits-fetters-are-more-in-our-mind/articleshow/75159905.cms

Q.30) 'MINUSCA' संयुक्त राष्ट्र का एक शांति मिशन, निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है?

a) सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक
b) डेमोक्रेटिक रीपब्लिक ऑफ द कॉंगो
c) बुर्किना फासो
d) सियरा लिओन

Q.30) Solution (a)

यह संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन है, जो 10 अप्रैल 2014 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत मध्य अफ्रीकी गणराज्य के नागरिकों की सुरक्षा के लिए आरंभ हुआ था।